



न्यू फ्रेंड्स गणेश उत्सव मंडल द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन



25 वर्षों से चल रही गणेश उत्सव स्थापना की परंपरा

बुलंद गोंदिया - गोंदिया शहर में गणेश उत्सव के आयोजनों की एक अपनी अलग ही पहचान बना चुके न्यू फ्रेंड्स गणेश उत्सव मंडल द्वारा गत 25 वर्षों से गणेश जी की स्थापना कर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। इस वर्ष पर्व के दौरान धार्मिक, सामाजिक, महाआरती, गरबा व बच्चों के लिए मनोरंजन के साथ विभिन्न स्वादिष्ट व्यंजनों के स्टाल लगाए गए हैं।

गौरतलब है कि गोंदिया शहर के गौशाला वार्ड के न्यू फ्रेंड्स गणेश उत्सव मंडल द्वारा गत 25 वर्षों से गणेश उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है जिसमें 10 दिनों तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही बप्पा की विदाई भव्य आतिशबाजी के साथ की जाती है। गत 2 वर्षों के कोरोना संक्रमण काल के पश्चात इस वर्ष न्यू फ्रेंड्स गणेश उत्सव मंडल द्वारा मंडल के संरक्षक राकेश ठाकुर के मार्गदर्शन में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जिसमें महिलाओं के लिए 2 सितंबर को हल्दी कुमकुम कार्यक्रम, दि. 4, 5 व 6 सितंबर को भव्य स्पेशल गरबा, 3 सितंबर को म्यूजिकल चेर, 7 सितंबर को ओपन हाउजी हाउसिंग जिसमें फ्रीडम फाइटर, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसके साथ ही 8 सितंबर को महाआरती व लक्की ड्रा आयोजित होने के साथ 9 सितंबर को हवन का आयोजन किया गया है। उपरोक्त पर्व के दौरान शहर के नागरिकों व श्रद्धालुओं से अधिक से अधिक आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होने का आवाहन न्यू फ्रेंड्स गणेश उत्सव मंडल के संरक्षक राकेश ठाकुर द्वारा किया गया है।

महिला चिकित्सालय की पुरानी इमारत के छज्जे का गिरा प्लॉस्टर

गर्भवती महिलाएं बाल-बाल बची, जनहानि नहीं



बुलंद गोंदिया - गोंदिया की शासकीय महिला चिकित्सालय की पुरानी इमारत जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, जिससे कभी भी एक बड़ा हादसा घटित हो सकता है। इसी के चलते मंगलवार 6 सितंबर को सुबह 11.30 बजे के दौरान सोनोग्राफी कक्ष के पास के बरामदे के छज्जे का प्लॉस्टर अचानक भरभरा कर गिर पड़ा। जिससे गर्भवती महिला बाल-बाल बची व किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई।

गौरतलब है कि गोंदिया के शासकीय महिला चिकित्सालय की पुरानी इमारत काफी खस्ताहाल स्थिति में हो चुकी है। जिस में बारिश के दौरान इमारत में पानी रिसने के साथ प्लॉस्टर उखड़ने की भी अनेक घटनाएं घटित होती हैं। इसी के चलते मंगलवार 6 सितंबर को सुबह 11.30 बजे के दौरान जब बड़ी संख्या में गर्भवती महिलाएं शासकीय महिला चिकित्सालय में सोनोग्राफी करवाने के लिए सोनोग्राफी कक्ष की ओर जा रही थी, तो इसी दौरान गेट के समीप स्थित छज्जे का प्लॉस्टर भरभरा कर गिर पड़ा। हालांकि इस घटना में किसी भी प्रकार की जान माल की हानि नहीं हुई। किंतु

भविष्य में कभी भी एक गंभीर हादसा हो सकता है। जिसके चलते उपरोक्त इमारत का सुधार कार्य करने के साथ-साथ जल्द ही उपरोक्त खस्ताहाल इमारत को गिराकर नई इमारत का निर्माण किया जाना अति आवश्यक है। अन्यथा भविष्य में कभी भी एक गंभीर घटना घटित हो सकती है। विशेष यह है कि उपरोक्त पुरानी इमारत में बच्चा वार्ड व गर्भवती महिला की सोनोग्राफी एक्सरे कक्ष है तथा बड़ी संख्या में नवजात शिशु व गर्भवती माताओं का यहां आना जाना लगा रहता है।

सार्वजनिक बांधकाम विभाग को किया सूचित
शासकीय महिला चिकित्सालय छज्जे का प्लॉस्टर गिरने की जानकारी प्राप्त होते ही इस संदर्भ में सार्वजनिक बांधकाम विभाग को सूचित कर जल्द से जल्द सुधार कार्य करने का पत्र दिया है। साथ ही इमारत में अन्य कहीं भी सुधार कार्य की आवश्यकता है तो उस पर भी जल्द ही कार्य किया जाएगा।
- डॉ.एस घोरपड़े, डीन शासकीय, मेडिकल कॉलेज गोंदिया

नराधम पिता ने बेटे को उतारा मौत के घाट

बुलंद गोंदिया - गोंदिया जिले के गोरगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम पिंडकेपार निवासी आरोपी लोकचंद बुरेले द्वारा अपने 40 वर्षीय बेटे कुलपत लोकचंद बुरेले की धारदार हथियार से वार कर जघन्य हत्या कर दी। हत्या का कारण यह था कि आरोपी अपनी पत्नी की पिटाई करता था। जिस पर बेटे द्वारा मां की पिटाई क्यों की? यह पूछे जाने पर आक्रोशित पिता ने इस जघन्य घटना को अंजाम दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरगांव तहसील के ग्राम पिंडकेपार निवासी मृतक कुलपत यह कोतवाल के रूप में पटवारी कार्यालय मुंडीपार में कार्य करता था। उसका पिता लोकचंद बुरेले यह झगड़ालू प्रवृत्ति व आक्रोशित स्वभाव का था। वह आए दिन अपनी पत्नी की किसी भी मामूली बात पर व घरेलू विवादों को लेकर पिटाई कर देता था। उसने जन्माष्टमी के समय अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी। जिसके पश्चात उसकी पत्नी मृतक के साथ न रहते हुए अपने छोटे बेटे राजेश के साथ रह रही थी। 31 अगस्त की शाम 7.30 बजे के दौरान आरोपी ने फिर से अपनी पत्नी के साथ मारपीट की। इस घटना को लेकर जब मृतक ग्राम के हनुमान मंदिर चौक पर मारपीट किए जाने का कारण पूछा तो आरोपी ने आक्रोशित होकर धारदार हथियार से अपने बेटे पर वार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। घटना के समय ग्राम के अनेक नागरिक वहां उपस्थित थे। उसका छोटा बेटा जब मजदूरी से वापस आया तो इस घटना की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचा व गंभीर अवस्था में जख्मी अपने भाई को चिकित्सालय ले गया। जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। घटना के पश्चात आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था। इस मामले में मृतक के भाई फरियादी राजेश बुरेले की शिकायत पर गोरगांव पुलिस थाने में भादवि की धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। जिसके पश्चात 1 सितंबर की शाम आरोपी को गोरगांव पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया, जहां 3 सितंबर तक उसे पुलिस हिरासत में भेजा गया।



लिम्फोमा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नामजद गोंदिया के सर्जन डॉ. विकास जैन ने फिर बनाया रेकॉर्ड महिला के पित्ताशय से निकाले १४२६ स्टोन

सबसे बड़ा ब्रेस्ट ट्यूमर निकालने का रिकॉर्ड भी दर्ज है डॉ. जैन के नाम

बुलंद गोंदिया - अपनी काबिलियत और बेहतर अनुभवी सुझाव से चिकित्सीय पेशे में दुनिया में नाम कमाने वाले शहर के बी.जे. हॉस्पिटल के सफलतम चिकित्सक डॉ. विकास जैन, फिर एक बार अपने कार्यों से चर्चा में हैं। इस बार डॉ. विकास जैन ने एक महिला के पेट में पित्ताशय की थैली का सफल ऑपरेशन कर 1426 पथरी निकाली है जो कि एक बड़ा रिकॉर्ड है।



इतनी बड़ी संख्या में पित्ताशय की थैली से स्टोन निकालना एक जटिल व चुनौतीपूर्ण कार्य था। परंतु हमेशा चुनौती स्वीकारने वाले डॉ. विकास जैन ने ये भी कर दिखाया और नया रिकॉर्ड कायम किया।
कहते हैं कि पित्ताशय की पथरी पित्त के कठोर क्रिस्टल बनने से होती है। पित्ताशय की थैली एक छोटा-सा नाशपती के आकार का अंग है, जो पेट के दाहिनी ओर यकृत के ठीक नीचे स्थित होता है। इसका काम पित्त को संग्रहित करना और छोड़ना होता है। जब पित्त में अतिरिक्त कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है तो यह क्रिस्टलाइज हो जाता है और पित्त पथरी बनने लगता है जो पित्ताशय की थैली को ठीक से खाली होने से रोकता है। ऐसा ही महिला के साथ हुआ। दो साल से ध्यान नहीं देने से ये घातक व असहनीय हो गया। जिसके बाद इसका सफल व जटिल ऑपरेशन किया गया।

बी.जे. हॉस्पिटल एन्ड रिसर्च इंस्टिट्यूट के प्रमुख डॉ. विकास जैन ने अब तक की सबसे बड़ी पथरी निकालकर लिम्फोमा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा चुके हैं। इतना ही नहीं डॉ. विकास जैन के नाम दुनिया में पहली बार सबसे बड़े ट्यूमर निकालने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने एक महिला पर जटिल व सफल ऑपरेशन कर 5.6 किलो का ब्रेस्ट ट्यूमर निकालकर रिकॉर्ड कायम किया था।
इस बार मध्यप्रदेश के बोदा, तहसील

मलाजखंड जिला बालाघाट की एक 55 वर्षीय महिला झुनबाई मडावी बी.जे. हॉस्पिटल में असहनीय दर्द लेकर आयी थी। डॉ. विकास जैन ने उनकी जांच कर अस्पताल में भर्ती होने कहा था। 31 अगस्त को महिला के पेट में पित्ताशय की थैली का जटिल ऑपरेशन किया गया। महिला के पित्ताशय से 1 हजार 4 सौ 26 छोटे-बड़े स्टोन निकाले गए। ये ऑपरेशन करीब कुछ घंटों तक चला एवं महिला 3 सितंबर को स्वस्थ होकर अपने घर लौट गई।

डांगोरली के बैरेंज के कार्य को मिली मंजूरी

गोंदिया शहरवासियों की पेयजल की और किसानों की सिंचाई समस्या होगी दूर

विधायक विनोद अग्रवाल के प्रयत्नों को मिली सफलता

बुलंद गोंदिया - गोंदिया विधानसभा क्षेत्र में तेहवा के पास डांगोरली बैराज का निर्माण महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों की मंजूरी से किया जाएगा और इससे तेहवा-सिवनी और नवेगांव-देवरी और डांगोरली उपसा सिंचाई योजनाओं को मजबूती मिलेगी। इससे जल संग्रहण और कृषि भूमि को लाभ होगा। किसानों के खेती के लिए उपयुक्त पानी और गोंदिया शहर के नागरिकों की पेयजल की समस्या का निराकरण किया जायेगा। इसके लिए विधायक विनोद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तथा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनसे चर्चा की थी। जिस पर मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। बैरेंज के निर्माण कार्य



को महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 की कलम 119 (च) के अनुसार मान्यता प्रदान की गई है। अगले चरण के डांगोरली बैरेंज के लिए सरकार की ओर से प्रशासकीय मान्यता लेकर बैरेंज का निर्माण कार्य जल्द ही शुरू किया जायेगा, विधायक विनोद अग्रवाल ने राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया।

विधायक विनोद अग्रवाल ने पिछले ढाई साल से हमेशा लोगों की समस्याओं का समाधान किया है और राजनीति की शुरुआत के बाद से उन्होंने ऐसे कई काम किए हैं। उनका पूरा जीवन सभी के कल्याण पर केंद्रित है और किसी को भी वंचित किए समाज में हर जरूरतमंद को कैसे लाभान्वित किया जाए। साथ ही विधायक बनने के बाद से उन्होंने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री तक डांगोरली बांध के निर्माण कार्य के लिए सतत मुख्यमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री से चर्चा की है और उन्हें इसमें सफलता भी मिली है। ग्रामीण भाग के किसानों के सिंचन की और शहरवासियों की पानी की समस्या का समाधान इस डांगोरली बैरेंज के निर्माण से होगा।

शिवसेना (शिंदे गट) के गोंदिया जिलाप्रमुख पद पर मुकेश शिवहरे की नियुक्ति



मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का माना आभार

बुलंद गोंदिया - शिवसेना के पूर्व गोंदिया जिला सहसंपर्क प्रमुख मुकेश शिवहरे ने विगत माह ही शिवसेना (उद्वव ठाकरे गट) से इस्तीफा देकर सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गट में शामिल होकर अपना समर्थन जाहिर किया था। शिवसेना शिंदे गट ने नागपुर में आयोजित प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुशांसा पर मुकेश शिवहरे को गोंदिया जिले की पुनः जिम्मेदारी देते हुए उन्हें शिवसेना (शिंदे गट) के गोंदिया जिलाप्रमुख पद पर नियुक्ति प्रदान की। इस नियुक्ति का पत्र सांसद कृपण तुमाने, विधायक आशीष जायसवाल, विधायक नरेंद्र भोंडेकर, पूर्व विधायक संपर्क नेता किरण पांडव की उपस्थिति में मुकेश शिवहरे को दिया गया। शिवहरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पर उनका हृदय से आभार माना एवं शिवसेना (शिंदे गट) को मजबूती प्रदान करने पक्ष की विचारधारा को बढ़ाने, सरकार के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने की भूमिका रखी।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का माना आभार बुलंद गोंदिया - शिवसेना के पूर्व गोंदिया जिला सहसंपर्क प्रमुख मुकेश शिवहरे ने विगत माह ही शिवसेना (उद्वव ठाकरे गट) से इस्तीफा देकर सैकड़ों समर्थकों के साथ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गट में शामिल होकर अपना समर्थन जाहिर किया था। शिवसेना शिंदे गट ने नागपुर में आयोजित प्रेस क्लब में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अनुशांसा पर मुकेश शिवहरे को गोंदिया जिले की पुनः जिम्मेदारी देते हुए उन्हें शिवसेना (शिंदे गट) के गोंदिया जिलाप्रमुख पद पर नियुक्ति प्रदान की। इस नियुक्ति का पत्र सांसद कृपण तुमाने, विधायक आशीष जायसवाल, विधायक नरेंद्र भोंडेकर, पूर्व विधायक संपर्क नेता किरण पांडव की उपस्थिति में मुकेश शिवहरे को दिया गया। शिवहरे ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारी पर उनका हृदय से आभार माना एवं शिवसेना (शिंदे गट) को मजबूती प्रदान करने पक्ष की विचारधारा को बढ़ाने, सरकार के कार्यों को जन-जन तक पहुंचाने की भूमिका रखी।

महाआरती के साथ पर्युषण पर्व उत्साह के साथ प्रारंभ

बुलंद गोंदिया - दिगंबर जैन समाज गोंदिया द्वारा बड़े उत्साह व धार्मिकता के साथ पर्युषण पर्व मनाया जा रहा है। जिसमें प्रतिदिन की आरती इस वर्ष के पर्युषण पर्व का विशेष आकर्षण है। इसके तहत महाआरती का सौभाग्य पर्युषण के प्रथम दिन पूर्व विधायक राजेन्द्र जैन के परिवार को प्राप्त हुआ। पूर्व विधायक राजेंद्र जैन के निवास स्थान से शाम 6.30 बजे महाआरती की शोभा यात्रा प्रारंभ होकर जैन समाज व बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी बंधुओं के साथ जैन मंदिर में पहुंची स मंदिर में विधिवत महाआरती करायी गई। यह पर्युषण पर्व में साधक विशेष साधना करते हैं यह पर्व नियम, संयम व तप धारण का पर्व है। इस अवसर पर पूर्व विधायक श्री राजेन्द्र जैन के पारिवारिक सदस्यों के साथ दिगम्बर जैन समाज के संजय जैन, अशोक ठोल्या, म्यानचंद पांड्या, वसंतकुमार



पांड्या, नरेश जैन, निखिल जैन, रोहित जैन, रवि कासलीवाल, देवेन्द्र अजमेरा, हिरेश जैन, राजु एन.जैन, बबला जैन, कमलेश खोखरे, नवल पुरोहित, देवेन्द्र अजमेरा, हिरेश जैन, हुक्क अग्रवाल, देवेन्द्रनाथ चौबे, नवीन जैन, प्रेम जायसवाल, संदीप जैन, तरुणकुमार अजमेरा, आनंद दयाचंद जैन, अक्षय

जैन, संकल्प जैन, निर्मल दयाचंद जैन, आनंद हिरालाल जैन, सुनील अग्रवाल, प्रकाश अग्रवाल, भूपेश चौबे, आशीष पांडेय, सन्नी जैन, राजेश कल्लू जैन, दिनेश अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, सुमेर जैन, आशिक जैन, विपुल जैन, अनिल जैन बेकरी, पिंठू जैन, सुनील जैन लगेज हाउस, आर्यन जैन, अनिल केशन तुरकर, रफीक खान, विनित सहारे, खालिद पठाण, साजन वाधवानी, लक्ष्मी रोचवानी, प्रकाश हसरानी, सुमित भालोटिया, बालकृष्ण पटले, चुन्नीभाऊ बेदरे, सुरेश टेटे, अमोल बेलगे, रवी मुंदडा, गुड्डू बिसेन, राहुल अग्रवाल, संदिप पटले, शिवम

संपादकीय

अवैध निर्माणों पर रोक लगे

नोएडा के विवादित ट्विन टावर के नौ सेकंड के अंदर रविवार दोपहर ढाई गिरा दिया गया। भ्रष्टाचार की तस्वीर बनकर खड़ी इन इमारतों को गिराने से जो संदेश दिया जाना था, वह दे दिया गया लेकिन अभी भी कई सवाल बाकी हैं जैसे क्या इन्हें गिराए जाए के अलावा कोई विकल्प नहीं था या इस प्रकरण में शामिल लोगों का क्या होगा ?

नोएडा के विवादित ट्विन टावर के नौ सेकंड के अंदर रविवार दोपहर ढाई बजे धूल-धूसरित होने की इमेज लंबे समय के लिए देशवासियों के जेहन में दर्ज हो गई। ट्विन टावर को गिराने की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक सरकारी एजेंसियों की देखरेख में और हर तरह की सतर्कता के साथ हुई। यही वजह रही कि दिल्ली की ऐतिहासिक कुतुबमीनार से भी ऊंची इन दोनों बिल्डिंगों को विस्फोटकों के जरिए ध्वस्त करने के बावजूद किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं होने दिया गया। हालांकि इसके संभावित परोक्ष दुष्प्रभावों के बारे में अभी से कोई नतीजा नहीं निकाला जा सकता, इसके लिए विशेषज्ञों को ज्यादा गहरी जांच-पड़ताल करनी होगी, जिसमें वक्त लगेगा। फिर भी यह नोएडा अथॉरिटी समेत तमाम एजेंसियों और विशेषज्ञ टीमों की सफलता कही जाएगी कि इस पूरी कवायद को ठीक उसी तरह अंजाम दिया गया जैसा कि तय हुआ था। यह ट्विन टावर वर्षों से विवादों में था और देश में बिल्डर-नौकरशाही-राजनेताओं की सांठगांठ का प्रतीक बन गया था।

पिछले कुछ समय से देश में यह आम धारणा बनती जा रही थी कि अपने यहां सब चलता है। नियम-कानूनों को धता बताते हुए जैसे भी हो जमीन लेकर बिल्डिंग खड़ी कर दो, एक बार फ्लैट्स बिक गए, लोग उसमें रहने लगे तो फिर कुछ नहीं होता। भ्रष्टाचार का टावर कहे जाने वाले इस ट्विन टावर को गिराए जाने से इस परसेप्शन को तोड़ने में थोड़ी मदद जरूर मिलेगी। लेकिन इस प्रकरण ने कई गंभीर सवाल उठाए हैं। एक तो यही कि अवैध बिल्डिंग तो गिरी, पर बिल्डिंग बनाने वालों का क्या? इस सिलसिले में पहली बात यह याद रखने की है कि बिल्डिंग को पूरी तरह से कंस्ट्रक्शन कंपनी के खर्च पर गिराया गया है। दूसरी और ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह कि इसे गलत तरीके से मंजूरी देने वाले भी कार्रवाई के दायरे में लिए गए हैं। कई अफसरों के खिलाफ कार्रवाई हुई है और जांच चल रही है। फिर भी यह बहस अपनी जगह है ही कि क्या पूरी तरह से तैयार ऐसी बिल्डिंगों को यों जमींदोज करना ही सबसे अच्छा विकल्प है? क्या सरकार द्वारा जब्त कर अस्पताल या किसी और ?प में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? सब जानते हैं कि नियम-कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए बनाई गई यह देश की इकलौती इमारत नहीं है। तो क्या बाकी इमारतों को भी इसी तरह ध्वस्त करना पड़ेगा? जाहिर है, ऐसी कार्रवाई सांकेतिक ही हो सकती है। सो इस ट्विन टावर के जरिए जो संदेश देना था, वह दिया जा चुका है। अब आगे का काम यह सुनिश्चित करना है कि इस संदेश को बिल्डर-अफसर-नेता बिरादरी गंभीरता से ग्रहण करे और अपने कार्य व्यवहार में आवश्यक बदलाव लाए।

व्यायाम के जरिए मांसपेशियों को सक्रिय बनाकर किए जाने वाले चिकित्सा की विधा शारीरिक चिकित्सा या फिजियोथेरेपी या फिजिकल थेरेपी कहलाती है। वास्तव में यह शारीरिक क्रिया चिकित्सा है। चूंकि इसमें दवाइयों नहीं लेना पड़ती इसलिए इनके दुष्प्रभावों का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फिजियोथेरेपी तब ही अपना असर दिखाती है जब इसे समस्या दूर होने तक नियमित किया जाए।

अगर शरीर के किसी हिस्से में दर्द है और आप दवाइयों नहीं लेना चाहते तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजियोथेरेपी की सहायता लेने पर आप दवा का सेवन किए बिना अपनी तकलीफ दूर कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट की सलाह अत्यंत आवश्यक है।

फिजिओथेरेपी का मतलब जीवन को पहचानना और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, साथ ही साथ लोगों को उनकी शारीरिक कमियों से बाहर निकालना, निवारण, इलाज बनाना और पूर्ण रूप से आत्म-निर्भर बनाना है। यह शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षेत्र में अच्छी तरह से काम करने में मदद देता है। फिजिओथेरेपी में डॉक्टर, शारीरिक चिकित्सक, मरीज, पारिवारिक लोग और दूसरे चिकित्सकों का बहुत योगदान होता है।

परिचय

शारीरिक चिकित्सा एक स्वास्थ्य प्रणाली है जिसमें लोगों का परीक्षण किया जाता है एवं उपचार प्रदान किये जाते हैं ताकि वे आजीवन अधिकाधिक गतिशीलता एवं क्रियात्मकता विकसित करें और उसे बनाये रख सकें। इसके अन्तर्गत वे उपचार आते हैं जिनमें व्यक्ति की गतिशीलता आयु, चोट, बीमारी एवं वातावरण सम्बन्धी कारणों से खतरे में पड़ जाती है।

शारीरिक चिकित्सा का सम्बन्ध जीवन की उत्कृष्टता एवं गतिशीलता के सामर्थ्य को पहचानने एवं उसको अधिकतम करने के साथ-साथ उसका प्रोत्साहन, बचाव, उपचार, सुधार एवं पुनर्स्थापना करने से है। इनमें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं सामाजिक कल्याण शामिल हैं। इसके अन्तर्गत शारीरिक चिकित्सक, मरीज ग्राहक, अन्य स्वास्थ्य व्यवसायी, परिवार, ध्यान रखने वालों और समुदायों के मध्य संपर्क की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें शारीरिक चिकित्सक के विशिष्ट ज्ञान और कुशलताओं द्वारा गतिशीलता की क्षमता का मूल्यांकन करके, सहमति के साथ उद्देश्य निर्धारित किये जाते हैं। शारीरिक चिकित्सा या तो शारीरिक चिकित्सक या उसकी देख-रेख में एक सहायक द्वारा की जाती है।

शारीरिक चिकित्सक किसी व्यक्ति के रोग का इतिहास जान कर और परीक्षण करके रोग की पहचान करने के बाद उपचार की योजना तैयार करते हैं और आवश्यक होने पर इसमें प्रयोगशाला एवं छवि (बिम्ब) परीक्षण भी सम्मिलित करवाते हैं। इस कार्य में वैद्युतिक निदानशास्त्र परीक्षण (इलेक्ट्रोडायग्नोस्टिक टेस्टिंग), उदाहरण के लिए इलेक्ट्रोमायोग्रैम्स और स्नायु-चलन वेग परीक्षण (नर्व कंडक्शन वेलोसिटी टेस्टिंग) भी उपयोगी हो सकती हैं।

शारीरिक चिकित्सा के कुछ विशेषज्ञता क्षेत्र हैं, जैसे कार्डियोपल्मोनरी चिकित्सा, जराचिकित्सा, स्नायु संबन्धी चिकित्सा, अस्थि-रोग चिकित्सा और बालरोग चिकित्सा इत्यादि। शारीरिक चिकित्सक कई प्रकार से कार्य करते हैं, जैसे, व्यापक रोगी क्लिनिक या कार्यालय, आंत्र-रोगी पुनर्वासि केन्द्र, निपुण परिचर्या सुविधाएं, प्रसारित संरक्षण केन्द्र, निजी घर, शिक्षा एवं शोध केन्द्र, स्कूल, मरणासन्न रोगी आश्रम, औद्योगिक अथवा अन्य व्यावसायिक

भौतिक चिकित्सा



कार्यक्षेत्र, फिटनेस केन्द्र तथा खेल प्रशिक्षण सुविधाएं आदि।

इनकी शैक्षिक योग्यताएं देशों के अनुसार भिन्न हैं। आवश्यक शैक्षिक योग्यता कुछ देशों में मामूली व्यावहारिक शिक्षा जबकि दूसरे देशों में परास्नातक या डॉक्टरेट की डिग्री हो सकती है।

इतिहास

हिप्पोक्रेटस और उसके बाद गेलेनस जैसे चिकित्सक शुरुआती शारीरिक चिकित्सकों में गिने जाते हैं, इन्होंने 460 ई.पू. में ही मालिश, हाथों से किये जाने वाले उपचार एवं जलचिकित्सा का समर्थन किया। अठारहवीं सदी में अस्थि-विज्ञान के विकास के बाद गठिया और उसके समान रोगों के उपचार के अन्तर्गत जोड़ों के सुनिर्वाहित व्यायाम हेतु जिमनेस्टीकॉन और ऐसी ही अन्य मशीनों का निर्माण होने लगा जो कि शारीरिक चिकित्सा में बाद में आए बदलावों के सद्सूत्र थे।

वास्तविक शारीरिक चिकित्सा का एक व्यवसाय समूह के रूप में सर्वाधिक प्राचीन प्रमाण के अनुसार वास्तविक शारीरिक चिकित्सा व्यवसाय समूह के रूप में मौलिक रूप से आरम्भ करने का श्रेय हेनरिक लिंग को जाता है, जिन्होंने रॉयल सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिमनेस्टिक्स की स्थापना 1813 में की, जहाँ पर मालिश, शारीरिक दक्ष-प्रयोग एवं व्यायाम होते थे। शारीरिक चिकित्सा के लिए स्वीडिश शब्द Sjuk gymnast बीमार-जिमनास्ट है। 1887 में, स्वीडन के नैशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एवं वेल्फेयर द्वारा शारीरिक चिकित्सकों को सरकारी पंजीकरण दिया जाने लगा।

अन्य देशों ने भी जल्दी ही इसका अनुसरण किया। ग्रेट ब्रिटेन में चार नर्सों के द्वारा 1894 में चार्टर्ड सोसईटी ऑफ फिजियोथेरेपी की स्थापना की गयी। 1913 में न्यूजीलैण्ड के ओटागो विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी ने और 1914 में संयुक्त राज्य अमेरिका के पोर्टलैंड, ओरिगोन के रीड कॉलेज ने

विश्व आत्महत्या निरोध दिवस

प्रतिवर्ष 10 सितंबर को मनाया जाने वाला यह दिवस विश्व में आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोकथाम लगाने एवं इस समस्या के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से शुरु किया गया था। इसे लोगों में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने और आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए मनाया जाता है। आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए इसे 2003 में शुरु किया गया था। विश्व आत्महत्या निरोध दिवस के अवसर पर चीनी व्याधि नियंत्रण और निरोध केंद्र के 2011 में जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया में अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए पहचाने जाने वाले चीन में हर साल करीब 20 लाख लोग आत्महत्या करते हैं। एक शोध के अनुसार चीन में आत्महत्या के मामलों में पिछले पांच दशकों में करीब 60 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। इसमें लगभग 75 प्रतिशत आत्महत्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। इन क्षेत्रों में महिलाओं में मौत की संख्या करीब 25 प्रतिशत ज्यादा है।

दुनिया भर में आत्महत्याओं की बढ़ती संख्या को रोकने और इसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम संघ (IASP) द्वारा 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस (World Suicide Prevention Day) मनाया जाता है।

डब्ल्यूएचओ की मांनें तो भारत में हर साल तकरीबन 1 लाख लोग खुदकुशी कर लेते हैं। बेरोजगारी, गरीबी, कर्ज तथा देश में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होना इसका मुख्य कारण हो सकता है।

10 सितम्बर 2022 को 20वां आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जा रहा है, इसे आत्महत्या निषेधनिवारणध्वचाव दिवस भी कहा जा सकता है

हर साल 10 सितंबर को दुनिया भर में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत वर्ष 2003 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रीवेंशन ने वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ के साथ मिलकर की थी।

इसका पहला साल सफल होने के बाद 2004 में WHO औपचारिक तौर पर इसका सह-प्रायोजक बना और इसे एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में पहचान मिली।

2016 की एक रिपोर्ट के मुताबिक खुदकुशी करने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 15 से 29 वर्ष के बीच बताई गई है, और इसके साथ ही इनमें से ज्यादातर लोग निम्न और मध्यमवर्गीय देशों से है जिनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा कम है।

क्यों मनाया जाता है?

वर्ल्ड सुसाइड प्रीवेंशन डे मनाने का मुख्य उद्देश्य आत्महत्या के बारे में जागरूकता बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर सुसाइड और इसके प्रयासों की संख्या को कम करना है। इसके साथ ही इसे रोकने के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा देना भी इसका मकसद है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हर सेकंड कोई ना कोई व्यक्ति खुदकुशी करने की कोशिश करता है, और हर 40 सेकंड में कोई ना कोई व्यक्ति अपनी जान का स्वयं दुश्मन बन बैठता है। इस तरह दुनियाभर में हर साल 7 लाख से ज्यादा लोग सुसाइड कर लेते हैं।

ऐसे में यह दिवस आत्मघाती विचारों से मुकाबला कर अपनी और दूसरों की सहायता कर उन्हें इससे बाहर निकालकर इन आंकड़ों को कम या खत्म करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

हर साल वर्ल्ड सुसाइड प्रीवेंशन डे एक खास विषय पर



आधारित होता है, संगठन ने 2021-2023 के कार्यक्रम की थीम क्रिएटिंग होप : एक्शन घोषित की है। इसलिए इस साल विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 की थीम कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना (Creating Hope Through Action) है।

कसो मनात है?

इस मौके पर लोगों को खुदकुशी करने से रोकने और आत्मघाती विचारों से मुकाबला करने के लिए विभिन्न अभियान चलाए जाते हैं।

इसकी शुरुआत के बाद से ही इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रीवेंशन हर साल इस खास दिन पर 60 से अधिक देशों में आत्महत्या को रोकने के लिए सैकड़ों कार्यक्रम आयोजित करता है।

यह दिवस अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खास थीम के साथ मनाया जाता है ताकि दुनिया भर के लोगों को इसके बारे में

शारीरिक पुनर्संरचना सहयोग में स्नातक उपाधि देना शुरु कर दिया।

अनुसंधानों ने शारीरिक चिकित्सा आंदोलन की गति बढ़ा दी। शारीरिक चिकित्सा का पहला शोध-पत्र संयुक्त राज्य अमरीका में 1921 में द पीटी रिव्यू में प्रकाशित हुआ। इसी वर्ष मेरी मैकमिलन ने फिजिकल थेरेपी एसोसियेशन, जिसे अब अमेरिकन फिजिकल थेरेपी एसोसियेशन) के नाम से जाना जाता है, की स्थापना की। 1924 में जॉर्जिया वार्म सिंग्र फाउंडेशन ने शारीरिक चिकित्सा को पोलियो के इलाज के रूप में प्रस्तुत करके इसे और प्रोन्नत किया।

1940 के दशक के उपचार माध्यमों में मुख्य रूप से व्यायाम, मालिश और कर्षण का प्रयोग होता था। रीड की हड्डि और अग्र-भाग के जोड़ों का अवस्था-अनुसार इलाज 1950 के दशक के शुरुआती वर्षों में, विशेष रूप से ब्रिटिश कामनवेल्थ देशों में प्रारम्भ हो गया था। इसी दशक के बाद के वर्षों में, शारीरिक चिकित्सक ने अपनी अस्पताल की सेवाओं से आगे बढ़ कर बाप-रोगी अस्थि-रोग क्लिनिक, सरकारी स्कूल, महाविद्यालय / विश्वविद्यालय, वृद्धों के लिए विशिष्ट परिचर्या सुविधाएं, पुनर्वासि केन्द्र, अस्पताल और चिकित्सा केन्द्रों में भी अपनी सेवाएं प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया।

शारीरिक शिक्षा में विशेषज्ञता 1974 में संयुक्त राज्य में प्रारम्भ हुई जब APTA ने उन शारीरिक चिकित्सकों, जो अस्थि-विज्ञान में दक्षता हासिल करना चाहते थे, उनके लिए अस्थि-विज्ञान विभाग की स्थापना की। इसी साल इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्थोपेडिक मेनुपुनेटिव थेरेपी की स्थापना की गयी और इसने तब से अब तक इस पद्धति की उन्नति में विशिष्ट भूमिका निभाई।

शिक्षा

वर्ल्ड कन्फेडरेशन ऑफ फिजिकल थेरेपी (WCPT) यह अनुभव करता है कि विश्व के शारीरिक चिकित्सकों की शिक्षा के परिवेश में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विविधता है। इसकी सिफारिश है कि शारीरिक चिकित्सकों का मूल-भूत शिक्षा कार्यक्रम विश्वविद्यालय स्तर पर कम से कम चार वर्षों का होना चाहिए, जिसको स्वतंत्र रूप से यह प्रमाणिकरण दिया जाये कि वह कार्यक्रम स्नातकों को पूरी तरह से वैधानिक और व्यावसायिक पहचान दिलाने में सक्षम है। WCPT स्वीकार करता है कि शिक्षा कार्यक्रम और प्रारम्भिक स्तरीय योग्यताओं के अन्तरण में नवीनता और भिन्नता है, जिसमें पहली विश्वविद्यालय उपाधियाँ (जैसे बैचलर / बैकेल्युरियेट / अनुज्ञापत्र प्राप्त या समकक्ष), परा-स्नातक और डॉक्टरेट की प्रारम्भिक योग्यताएं सम्मिलित हैं। उम्मीद यह की जाती है कि कोई भी शैक्षणिक कार्यक्रम, इन दिशानिर्देशों का पालन करते हुए, शारीरिक शिक्षकों को उनके पेशे से सम्बन्धित ज्ञान, कुशलता और विशेषता प्रदान करेगा।

व्यावसायिक शिक्षा इन शारीरिक चिकित्सकों को, हेल्थ-केयर दल के अन्य सदस्यों के समकक्ष निपुण, स्वतन्त्र पेशेवर बनने के लिए तैयार करती है।

शारीरिक चिकित्सकों के प्रवेश-स्तर पर के शैक्षणिक कार्यक्रमों में शैक्षणिक सततता के साथ-साथ सिद्धान्त, प्रमाण और अभ्यास का एकीकरण होता है। यह एक मान्यता प्राप्त शारीरिक चिकित्सा कार्यक्रम में प्रवेश के साथ शुरु होता है और सक्रिय अभ्यास से सेवानिवृत्त होने के साथ समाप्त होता है।

यूएस में शारीरिक चिकित्सकों के 211 मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों में से 202 को डॉक्टरेटस्तर तक मान्यता प्राप्त है। वहां डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी (DPT) की उपाधि प्रदान करते हैं।

जागरूक किया जा सके और उन्हें इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा सके।

आत्महत्या करने के लक्षण और बचाव क्या है?

रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 81 प्रतिशत सुसाइड करने वाले लोग कुछ ऐसे संकेत जरूर देते हैं जिन्हें हमें समझ जाना चाहिए। ये हैं कुछ ऐसे ही सवाल :

- मेरे जाने के बाद आपको दुख होगा?
- क्या आप मेरे बिना जी लेंगे?
- मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है?
- मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा?

लक्षण?

यदि कोई व्यक्ति इस दौर से गुजर रहा है तो उसमें निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं :

- वह अचानक नशे की मात्रा बढ़ा देते हैं।
- मरने की बातें बार-बार करते हैं।
- आत्मलानि की बातें करते हैं।
- वे अक्सर उदास या गुमसुम रहने लगते हैं।

- लापरवाही बरतते हैं और खुद की जान हमेशा जोखिम में डालने लगते हैं।

ऐसे में हमें समझ जाना चाहिए और उनसे खुलकर बात करनी चाहिए। जब वह आपको अपनी फिलिंस् के बारे में बताना शुरू करे तो यह जरूरी है कि आप उसे ध्यान से सुने।

इस दौरान कोई भी नकारात्मक बात ना करें और सकारात्मकता से उसे समझाने और उसकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करें। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अकेला ना छोड़ें।

आत्महत्या का मुख्य कारण क्या है?

वैसे तो आत्महत्या मनोवैज्ञानिक, संस्कृतिक, अनुवांशिक, सामाजिक और कई अन्य जोखिमों के अभिसरण का परिणाम होता है। परंतु हर साल खुदकुशी करने वाले लाखों लोग अलग-अलग कारणों से मौत को अपने गले लगाते हैं।

इसके कुछ सामाजिक कारकों में घरेलू झगड़े, कर्ज, गरीबी, बेरोजगारी, दहेज, प्रेम संबंध, तलाक, अनुचित गर्भधारण, विवाहतर संबंध, वैवाहिक अडचन या शैक्षिक समस्या हो सकती है।

वैसे तो खुदकुशी करने वाले लोगों इसके लिए कई अलग-अलग तरीके तलाशते हैं परंतु अधिकतर मामलों में यह देखा गया है कि लोग अपनी जीवन लीला समाप्त करने के लिए ज्यादातर फांसी, जहरीला पदार्थ और धारदार चीज या बंदूक का इस्तेमाल करते हैं।

सेना में महिला शक्ति

आईएनएस विक्रांत को नौसेना को समर्पित करते हुए पीएम मोदी ने देश की महिला शक्ति का जिक्र किया। नौसेना ने सभी ब्रांच महिलाओं के लिए खोलने का फैसला कर लिया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को देश में बना पहला विमानवाहक पोत आईएनएस विक्रांत नौसेना को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिला शक्ति को नौसेना की शक्ति के साथ सांकेतिक तौर पर मिलाते हुए कहा कि आईएनएस विक्रांत जब हमारे समुद्री इलाके की रक्षा करने उतरेगा तो उस पर महिला सैनिक भी होंगी। उनके शब्दों में, सागर की निस्सीम शक्ति के साथ असीम महिला शक्ति अब नए भारत की पहचान होगी। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि नौसेना ने सभी ब्रांच महिलाओं के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। यह बड़ी घोषणा इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ समय से किए गए अथक प्रयासों के बावजूद भारतीय सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है।

ध्यान रहे, आर्मी और एयरफोर्स के मुकाबले नेवी में महिलाओं की मौजूदगी अच्छी है, लेकिन वहां भी यह महज 6.5 फीसदी है। प्रसंगवश एयरफोर्स में महिलाओं का प्रतिशत 1.08 फीसदी है और आर्मी में महज 0.56 फीसदी। बेशक सशस्त्र सेनाओं को दुनिया भर में पुरुषों का क्षेत्र माना जाता रहा है, लेकिन इसमें महिलाओं की संख्या हर जगह इतनी कम नहीं है। उदाहरण के लिए, 2020 में यूएस मिलिटरी अकैडमी में 23 फीसदी कैडेट महिलाएं थीं। भारत में सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं की कम संख्या की एक वजह शायद यह है कि यहां नर्सिंग जैसी शाखाओं को छोड़ दें तो महिलाओं को प्रवेश भी देर से मिला। लेकिन यह बात भी सही है कि वहां उनकी भूमिकाएं भी सीमित ही रही।

होना तो यह चाहिए था कि उन्हें नई-नई भूमिकाओं में खुद को आजमाने और कठिन चुनौतियों को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता, लेकिन कई मामलों में इसका उलटा देखने को मिला। हालांकि इसके पीछे किसी तरह की दुर्भावना के बजाय समाज की पितृसत्तात्मक सोच और महिलाओं की सुरक्षा की चिंता का ही ज्यादा रोल रहा, लेकिन फिर भी यह सचाई है कि सशस्त्र सेनाओं में महिलाओं ने जो उपलब्धियां अपने नाम दर्ज की हैं और जिस तरह से अपने लिए स्पेस क्रिएट करती जा रही हैं उसका सबसे ज्यादा श्रेय पुरुष वर्चस्व वाले इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाली पहली और दूसरी पीढ़ी की महिलाओं को और देश की न्यायपालिका को जाता है।

सुप्रीम कोर्ट ने समय-समय पर दखल देकर महिलाओं के लिए यहां लेवल प्लेइंग फील्ड सुनिश्चित करने की कोशिश की है। हालांकि अब भी महिलाओं को आर्मी में कॉम्बैट रोल नहीं दिया जा रहा, लेकिन पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बढौतत प्रतिष्ठित नेशनल डिफेंस अकैडमी की प्रवेश परीक्षा में बैठने की इजाजत पा लेने के बाद अब महिलाएं सेना के विभिन्न मोर्चों पर खुद को साबित करने में पीछे नहीं रहेंगी। ऐसे में प्रधानमंत्री की ताजा घोषणा ने केवल सशस्त्र सेनाओं के अंदर सेवा दे रही महिलाओं को बल्कि इसका सपना देख रही लड़कियों को भी ताकत देगी।

पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रान्त के जलावतरण से बढ़ी रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता



बुलंद गोंदिया - देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रान्त के जलावतरण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जो ऐसे पोत स्वयं बना सकने में सक्षम हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री ने आइएनएस विक्रान्त को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का परिचायक बताया।

देश के पहले स्वदेशी विमानवाहक पोत आइएनएस विक्रान्त के जलावतरण के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जो ऐसे पोत स्वयं बना सकने में सक्षम हैं। इसी कारण प्रधानमंत्री ने आइएनएस विक्रान्त को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का परिचायक बताया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता समय की एक ऐसी मांग है, जिसे पूरा करने के लिए न केवल ह्रासंभव प्रयास किए जाने चाहिए, बल्कि इस उद्देश्य के तहत काम किया जाना चाहिए कि भारत रक्षा सामग्री और उपकरणों का आयातक बनने के बजाय निर्यातक बने।

यह केवल इसलिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि भारत उन देशों में शामिल है, जो अधिकांश रक्षा सामग्री आयात करता है, बल्कि इसलिए भी है, क्योंकि सैन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। यदि देश अपनी रक्षा आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो सके तो

हथियारों की खरीद में खर्च होने वाले धन को देश के विकास में लगा सकता है। रक्षा जरूरतों के मामले में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता इसलिए भी बढ़ गई है, क्योंकि कई बार जरूरी रक्षा सामग्री समय पर नहीं मिल पाती।

भारत अपनी अधिकांश रक्षा जरूरतों के लिए उस रुस पर निर्भर है, जो यूक्रेन युद्ध के बाद से चीन के निकट जा रहा है। चूंकि इसका कोई पता नहीं कि यूक्रेन युद्ध कब समाप्त होगा, इसलिए यह आशंका बढ़ गई है कि भारत को रुस से रक्षा सामग्री और उपकरण हासिल करने में कठिनाई और देरी का सामना करना पड़ सकता है। इस सिलसिले में यह भी किसी से छिपा नहीं कि रक्षा सौदों को अंतिम रूप देने में अच्छा-खासा समय लग जाता है। इसके चलते कई बार सेनाओं को समय पर रक्षा सामग्री नहीं मिल पाती।

एक ऐसे समय जब चीन शत्रुतापूर्ण रवैया अपनाए हुए है और इसके कोई आसार नहीं कि वह सीमा पर तनाव खत्म करने का इच्छुक है, तब यह कहीं अधिक आवश्यक है कि भारत अपनी सेनाओं को किसी भी खतरों का सामना करने के लिए तैयार रखे। जैसे चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वैसे ही पाकिस्तान पर भी। ये दोनों देश भारतीय हितों के खिलाफ काम करने में लगे हुए हैं। इसे देखते हुए भारत को अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के मामले में तत्परता का परिचय देना होगा।

एक ऐसे समय जब भारत ने अगले 25 वर्षों में स्वयं को विकसित देश के रूप में उभारने का लक्ष्य रखा है, तब यह और आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी रक्षा जरूरतों के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर बनने की ठोस रूपरेखा बनाए। ध्यान रहे कि कोई देश वास्तव में विकसित तभी बनता है, जब वह रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होता है।

खुदकुशी का रास्ता

राष्ट्रीय अपराध रेकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) ने देश में खुदकुशी के जो ताजा आंकड़े जारी किए हैं, वे चौंकाने वाले हैं। आंकड़े बता रहे हैं कि 2021 में खुदकुशी करने वालों की संख्या और इसकी दर दोनों में भारी इजाफा हुआ। साल 1967 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब आत्मघाती कदम उठाने की प्रवृत्ति इतनी तेजी से बढ़ी।

एनसीआरबी के मुताबिक साल 2021 में खुदकुशी करने वालों का आंकड़ा प्रति दस लाख पर 120 तक पहुंच गया, जो 2020 की तुलना में 6.1 फीसद ज्यादा रहा। लेकिन इससे भी ज्यादा जो चिंताजनक बात सामने आई, वह यह कि पिछले साल खुदकुशी करने वाला हर चौथा व्यक्ति दिहाड़ी मजदूर था। आंकड़े बता रहे हैं कि साल 2019 से 2021 के बीच गरीब तबके में खुदकुशी की घटनाएं ज्यादा तेजी से बढ़ीं। इससे पता चलता है कि देश का गरीब तबका किस कदर बढ़ावाली में जी रहा है। खुदकुशी के ये आंकड़े सरकार और समाज के समक्ष गंभीर सवाल खड़े करते हैं।

अगर लोग मौत को गले लगाने को मजबूर हो रहे हैं तो निश्चित ही कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार कारण हमारे समाज और सरकारों की नीतियों के भीतर ही मौजूद हैं। इससे यह भी पता चलता है कि एक कल्याणकारी राज्य में सरकारें अपने नागरिकों के प्रति कितनी लापरवाह हो जाती हैं और समाज संवेदनहीन।

एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि 2019 से 2021 के दौरान खुदकुशी करने वालों में दिहाड़ी मजदूरों के अलावा छात्रों, स्वरोजगार में लगे लोगों, वेतनभोगियों और सेवानिवृत्त लोग भी कम नहीं थे। साल 2021 में एक लाख चौरसठ हजार तैतीस लोगों ने खुदकुशी की। इनमें दिहाड़ी मजदूरों की संख्या ब्यालीस हजार के लगभग रही, यानी खुदकुशी करने वालों की कुल संख्या का एक चौथाई। इससे पिछले साल यानी 2020 में सैंतीस हजार छह सौ छियासठ दिहाड़ी मजदूरों ने खुदकुशी की थी।

गौरतलब है कि 2019 से 2021 की अवधि कोरोना महामारी वाली रही। उस दौरान देश में पूर्णबंदी और फिर लंबे समय तक चले आंशिक प्रतिबंधों ने छोटे-बड़े कारोबारों को चौपट कर डाला था। मार्च-अप्रैल 2019 में तो करोड़ों प्रवासी कामगारों को अपने घरों को लौटने को मजबूर होना पड़ा था। एक साथ करोड़ों लोगों का रोजगार से हाथ धो बैठना कोई मामूली घटना नहीं कही जा सकती। इसमें सबसे ज्यादा दिहाड़ी मजदूर ही थे।

हालांकि निजी क्षेत्र में काम करने वाले लाखों वेतनभोगी भी महामारी से उत्पन्न हालात के शिकार हुए। इस बढ़ावाली का असर आज भी बना हुआ है। जाहिर सी बात है कि अगर लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा और लोग खाएंगे क्या। दिहाड़ी मजदूरों के सामने यही संकट दो साल पहले भी था और कर्मोबेश आज भी बना हुआ है।

आंकड़े बता रहे हैं कि दिहाड़ी मजदूरों, स्वरोजगार में लोगों, पेशेवरों आदि में खुदकुशी करने वालों में दो तिहाई लोग ऐसे थे जिनकी सालाना आय एक लाख रुपए या इससे भी कम थी। भले केंद्र और राज्य सरकारें दावे करती रहें कि गरीब तबके को बचाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, करोड़ों लोगों को महीनों तक मुफ्त राशन या खाना दिया, लेकिन असलियत किसी से छिपी नहीं है।

अभी भी सरकारों की तरफ से रोजगार के मोर्चे पर हालात बेहतर होने के दावे किए जा रहे हैं। अगर वाकई रोजगार के हालात अच्छे हैं तो लोग जान देने पर क्यों मजबूर हैं? आज महंगाई और बेरोजगारी ने गरीब और मध्यवर्ग को बेहाल कर दिया है। ऐसे में जिसके पास खाने को नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा या भारी कर्ज में दबा होगा, तो वह खुदकुशी जैसा कदम उठाने को ही मजबूर होगा!

गोंदिया सरकारी तकनीकी संस्थान को मिला उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा

सभी शाखाओं को किया अपडेट, शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि

बुलंद गोंदिया - महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, मुंबई बोर्ड के तहत सभी डिग्री पाठ्यक्रमों का वार्षिक शैक्षणिक पर्यवेक्षण करता है। शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक शैक्षणिक निरीक्षण मई माह में आयोजित किया गया था। इस अवसर पर महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, मुंबई द्वारा नियुक्त विभिन्न दल ने गोंदिया और भंडारा जिलों में कुल 24 संस्थानों में शैक्षिक निरीक्षण किया गया। इसमें गोंदिया सरकार तंत्र निकेतन की सभी शाखाएं उत्कृष्ट गुणवत्ता की रही हैं और इस संस्थान को उत्कृष्ट संस्थान रेटिंग मिली है।

शैक्षिक निरीक्षण में बुनियादी सुविधाओं, छात्र परिणाम, प्लेसमेंट, प्रयोगशालाओं, व्याख्याताओं की संख्या, व्याख्याताओं की शैक्षणिक योग्यता, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया और अन्य सभी मापदंडों की शाखावार जांच की जाती है। सरकारी तन्त्रनिकेतन, गोंदिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, परमाणु ऊर्जा और दूरसंचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग और सूचना प्रौद्योगिकी शाखाओं में कुल 6 शाखाएं हैं, जिन्होंने पिछले शैक्षणिक निरीक्षण में उत्कृष्ट स्थिति प्राप्त की है, इसलिए उनके इस वर्ष शैक्षणिक निरीक्षण नहीं किया गया।

शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, परमाणु ऊर्जा और दूरसंचार इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग शाखाएं अकादमिक पर्यवेक्षण के अधीन थीं। इसमें

मेरे बलिराज के लिए मेरा एक दिन अभियान १ सितंबर से ३० नवंबर तक

बुलंद गोंदिया - प्रशासन को किसानों की समस्याओं और मुद्दों को समझना चाहिए, उपाय करना चाहिए और उन पर निर्णय लेना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए 1 सितंबर से 30 नवंबर, 2022 तक, जिला और तहसील स्तर के अधिकारियों और प्रशासन के अधिकारियों ने श्रमाई वन डेश पहल के तहत सरकारी परिपत्र के अनुसार किसानों की समस्याओं को समझने के लिए किसानों के साथ पूरा दिन बिताया। मेरे बलिराज अभियान के लिए गोंदिया तहसील के गर्गा गांव से शुरु हुआ।

जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी हिंदूराव चव्हाण, वरिष्ठ शोधकर्ता केवीके डॉ सैयद अली, तहसील कृषि अधिकारी धनराज तुमदाम, कृषि अधिकारी पवन

सभी शाखाओं को उत्कृष्ट दर्जा प्राप्त है। गोंदिया सरकारी तकनीकी संस्थान की सभी 6 शाखाओं को महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड, मुंबई द्वारा उत्कृष्ट दर्जा दिया गया है। सरकारी तकनीकी संस्थान गोंदिया और भंडारा जिले में एकमात्र संस्थान है जहां सभी शाखाएं उत्कृष्ट हैं। यह जानकारी एकेडमिक को-ऑर्डिनेटर प्रो. नितिन गुल्हाने ने दिया।

1) डॉ. सी.डी. गोलघाट, प्राचार्य, शासकीय तकनीकी संस्थान, गोंदिया- संस्था लगातार प्रगतिशील है। उद्देश्य भविष्य में संगठन को महाराष्ट्र में नंबर एक बनाना है।

2) डॉ. राम निबुडे, विभागाध्यक्ष, सिविल इंजीनियरिंग- सिविल इंजीनियरिंग विभाग में उच्च योग्य संकाय के साथ-साथ अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं हैं और छात्रों के समग्र विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं। वास्तुकला के 95 प्रतिशत छात्र उच्च शिक्षा के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं। इस विभाग के माध्यम से अन्य सरकारी विभागों को निर्माण परामर्श सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों को भी लाभ होता है।

3) डॉ. प्रशांत शर्मा, विभागाध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा एवं दूरसंचार अभियांत्रिकी- त्रयह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि गोंदिया संभाग के छात्रों के लिए सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालय, गोंदिया जैसी संस्था एक वरदान है। उच्च शैक्षणिक और तकनीकी गुणवत्ता के लिए सभी सुविधाएं, अनुभवी शिक्षक संस्थान की



मेथ्राम, फसल बीमा कंपनी के राज्य समन्वयक प्रकाश श्रीवास्तव ने गतिविधि शुरु करने के लिए गर्गा गांव का दौरा किया। ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ग्रामीणों ने ग्रामीणों से बातचीत कर समस्याओं व समस्याओं का समाधान किया। इस

पहचान है। साथ ही, छात्रों के समग्र व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है।

4) डॉ. गजानन गोटमारे, विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियांत्रिकी- विद्युत अभियांत्रिकी विभाग में कुल छह सुसज्जित प्रायोगिक विद्यालय हैं, इस वर्ष अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली (एआईसीटीई) से एक प्रयोगशाला के लिए धन प्राप्त हुआ है। साथ ही एआईसीटीई ट्रेनिंग एंड लर्निंग (एटीएल) अकादमी के माध्यम से प्राप्त धनराशि से राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।

विभाग छात्रों की शैक्षणिक उन्नति के लिए प्रतिबद्ध है।

5) प्रो. गुलाब दहोल, विभागाध्यक्ष, यांत्रिक अभियांत्रिकी - को योग्य संकाय और कर्मचारियों के साथ यांत्रिक अभियांत्रिकी विभाग को निर्देशित करने का सम्मान प्राप्त है। महाराष्ट्र राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा तैयार किए गए शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए छात्रों को इस संस्थान में प्रेरित किया जाता है।

6) प्रो. स्वप्निल अंबाडे, एकेडमिक कोऑर्डिनेटर- प्राचार्य, विभागाध्यक्ष, प्राध्यापक, कर्मचारी और संस्थान के छात्र किसी भी संस्थान को उत्कृष्ट बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि इस संस्थान की जनशक्ति और छात्र उत्कृष्ट हैं, इसलिए संस्थान को उत्कृष्ट रेटिंग मिली है। इस रेटिंग को बरकरार रखने के साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा।

कार्यक्रम में फसल बीमा योजना में भाग लेने वाले किसानों को सम्मानित किया गया। उपस्थित सभी लोगों को महा डीबीटी, धान की फसलों पर कीट रोग प्रबंधन, मग्रोमो बागों का रोपण, प्रधानमंत्री सुषमा खाद्य उद्योग योजना, तुषार थिबक संच पंजीकरण, रबी योजना, कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के बारे में निर्देशित किया गया।

सरापंच कुलदीप पटले, पीएस चैयरमैन मुनेश्वर रहांगडाले, पीएस सदस्य सुनीता दिहारी, उपसरपंच आशीष मिश्रा, मंडल कृषि अधिकारी पवार, कृषि पर्यवेक्षक मंडे, सहायक लिहारे, माविम और उमेद की महिलाएं, किसान और ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

हिन्दी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को मनाया जाता है। 14 सितम्बर 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिन्दी केन्द्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिन्दी भाषा बोली जाती थी इसलिए हिन्दी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिन्दी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिये वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितम्बर को प्रतिवर्ष हिन्दी-दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद हिन्दी को आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित करवाने के लिए काका कालेलकर, हजारीप्रसाद द्विवेदी, सेंट गोविन्ददास आदि साहित्यकारों को साथ लेकर व्यौहार राजेन्द्र सिंह ने अथक प्रयास किये।

इतिहास

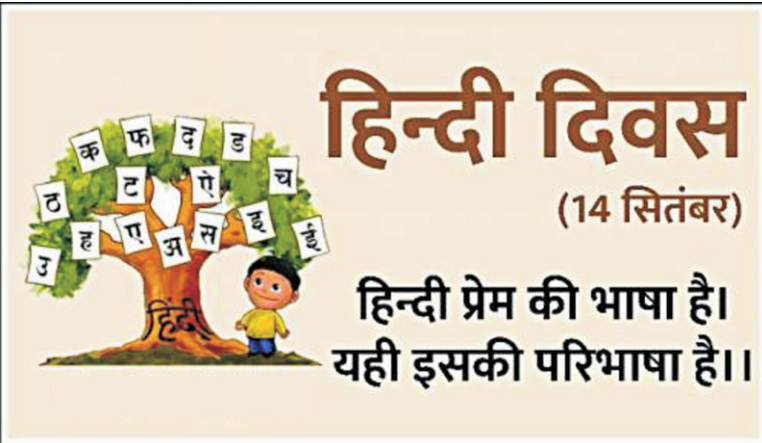
वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन में हिन्दी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत की राजभाषा के प्रश्न पर 14 सितम्बर 1949 को काफी विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया जो भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय की अनुच्छेद 343(1) में इस प्रकार वर्णित है। संघ की राजभाषा हिन्दी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप अन्तरराष्ट्रीय रूप होगा।

यह निर्णय 14 सितम्बर को लिया गया, इसी दिन हिन्दी के मूर्धन्य साहित्यकार व्यौहार राजेन्द्र सिंहा का 50वाँ जन्मदिन था, इस कारण हिन्दी दिवस के लिए इस दिन को श्रेष्ठ माना गया था। हालांकि जब राष्ट्रभाषा के रूप में इसे चुना गया और लागू किया गया तो अ-हिन्दी भाषी राज्य के लोग इसका विरोध करने लगे और अंग्रेजी को भी राजभाषा का दर्जा देना पड़ा। इस कारण हिन्दी में भी अंग्रेजी भाषा का प्रभाव पड़ने लगा।

कार्यक्रम

हिन्दी दिवस के दौरान कई कार्यक्रम होते हैं। इस दिन छात्र-छात्राओं को हिन्दी के प्रति सम्मान और दैनिक व्यवहार में हिन्दी के उपयोग करने आदि की शिक्षा दी जाती है। जिसमें हिन्दी निबन्ध लेखन, वाद-विवाद हिन्दी टंकण प्रतियोगिता आदि होता है। हिन्दी दिवस पर हिन्दी के प्रति लोगों को प्रेरित करने हेतु भाषा सम्मान की शुरुआत की गई है। यह सम्मान प्रतिवर्ष देश के ऐसे व्यक्तित्व को दिया जाएगा जिसने जन-जन में हिन्दी भाषा के प्रयोग एवं उत्थान के लिए विशेष योगदान दिया है। इसके लिए सम्मान स्वरूप एक लाख एक हजार रुपये दिये जाते हैं। हिन्दी में निबन्ध लेखन प्रतियोगिता के द्वारा कई जगह पर हिन्दी भाषा के विकास और विस्तार हेतु कई सुझाव भी प्राप्त किए जाते हैं। लेकिन अगले दिन सभी हिन्दी भाषा को भूल जाते हैं। हिन्दी भाषा को कुछ और दिन याद रखें इस कारण राष्ट्रभाषा सप्ताह का भी आयोजन होता है। जिससे यह कम से कम वर्ष में एक सप्ताह के लिए तो रहती ही है।

हिन्दी दिवस पर हिन्दी निबन्ध लेखन, वाद-विवाद, विचार गोष्ठी, काव्य गोष्ठी, श्रुतलेखन प्रतियोगिता, हिन्दी टंकण प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, पुरस्कार समारोह, राजभाषा सप्ताह



का आयोजन किया जाता है।

बोलने वालों की संख्या के अनुसार अंग्रेजी और चीनी भाषा के बाद हिन्दी भाषा पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी भाषा है। लेकिन उसे अच्छी तरह से समझने, पढ़ने और लिखने वालों में यह संख्या बहुत ही कम है। यह और भी कम होती जा रही। इसके साथ ही हिन्दी भाषा पर अंग्रेजी के शब्दों का भी बहुत अधिक प्रभाव हुआ है और कई शब्द प्रचलन से हट गए और अंग्रेजी के शब्द ने उसकी जगह ले ली है। जिससे भविष्य में भाषा के विलुप्त होने की भी संभावना अधिक बढ़ गयी है।

इस कारण ऐसे लोग जो हिन्दी का ज्ञान रखते हैं या हिन्दी भाषा जानते हैं, उन्हें हिन्दी के प्रति अपने कर्तव्य का बोध करवाने के लिए इस दिन को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है जिससे वे सभी अपने कर्तव्य का पालन कर हिन्दी भाषा को भविष्य में विलुप्त होने से बचा सकें। लेकिन लोग और सरकार दोनों ही इसके लिए उदासीन दिखती हैं। हिन्दी तो अपने घर में ही दासी के रूप में रहती है। हिन्दी को आज तक संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा नहीं बनाया जा सका है। इसे विडम्बना ही कहेंगे कि योग को 177 देशों का समर्थन मिला, लेकिन हिन्दी के लिए 129 देशों का समर्थन क्यों नहीं जुटाया जा सकता? इसके ऐसे हालात आ गए हैं कि हिन्दी दिवस के दिन भी कई लोगों को दिवटर पर हिन्दी में बोले जैसे शब्दों का उपयोग करना पड़ रहा है। अमर उजाला ने भी लोगों से विनती की कि कम से कम हिन्दी दिवस के दिन हिन्दी में ट्वीट करें।

उद्देश्य

इसका मुख्य उद्देश्य वर्ष में एक दिन इस बात से लोगों को रुबरु कराना है कि जब तक वे हिन्दी का उपयोग पूरी तरह से नहीं करेंगे तब तक हिन्दी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। इस एक दिन सभी सरकारी कार्यालयों में अंग्रेजी के स्थान पर हिन्दी का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा जो वर्ष भर हिन्दी में अच्छे विकास कार्य करता है और अपने कार्य में हिन्दी का अच्छी तरह से उपयोग करता है, उसे पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया जाता है।

कई लोग अपने सामान्य बोलचाल में भी अंग्रेजी भाषा के शब्दों का या अंग्रेजी का उपयोग करते हैं, जिससे धीरे धीरे हिन्दी के अस्तित्व को खतरा पहुँच रहा है। जिस तरह से टेलीविजन से लेकर विद्यालयों तक और सोशल मीडिया से लेकर निजी तकनीकी संस्थानों एवं निजी दफ्तरों तक में अंग्रेजी का दबदबा कायम है। उससे लगता है कि अपनी मातृभाषा हिन्दी

धीरे-धीरे कम और फिर दशकों बाद विलुप्त न हो जाये। यदि शीघ्र ही हम छोटे-छोटे प्रयासों द्वारा अपनी मातृभाषा हिन्दी को अपने जीवन में एक अनिवार्य स्थान नहीं देंगे तो यह दूसरी भाषाओं से हो रही स्पर्धा में बहुत पीछे रह जायेगी। यहाँ तक कि वाराणसी में स्थित दुनिया में सबसे बड़ी हिन्दी संस्था आज बहुत ही खस्ता हाल में है। इस कारण इस दिन उन सभी से निवेदन किया जाता है कि वे अपने बोलचाल की भाषा में भी हिन्दी का ही उपयोग करें। इसके अलावा लोगों को अपने विचार आदि को हिन्दी में लिखने भी कहा जाता है। चूँकि हिन्दी भाषा में लिखने हेतु बहुत कम उपकरण के बारे में ही लोगों को पता है, इस कारण इस दिन हिन्दी भाषा में लिखने, जाँच करने और शब्दकोश के बारे में जानकारी दी जाती है। हिन्दी भाषा के विकास के लिए कुछ लोगों के द्वारा कार्य करने से कोई खास लाभ नहीं होगा। इसके लिए सभी को एक जुट होकर हिन्दी के विकास को नए आयाम तक पहुँचाना होगा। हिन्दी भाषा के विकास और विलुप्त होने से बचाने के लिए यह अनिवार्य है।

हिन्दी सप्ताह

हिन्दी सप्ताह 14 सितम्बर से एक सप्ताह के लिए मनाया जाता है। इस पूरे सप्ताह अलग-अलग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। यह आयोजन विद्यालय और कार्यालय दोनों में किया जाता है। इसका मूल उद्देश्य हिन्दी भाषा के लिए विकास की भावना को लोगों में केवल हिन्दी दिवस तक ही सीमित न कर उसे और अधिक बढ़ाना है। इन सात दिनों में लोगों को निबन्ध लेखन, आदि के द्वारा हिन्दी भाषा के विकास और उसके उपयोग के लाभ और न उपयोग करने पर हानि के बारे में समझाया जाता है।

पुरस्कार

हिन्दी दिवस पर हिन्दी के प्रति लोगों को उत्साहित करने हेतु पुरस्कार समारोह भी आयोजित किया जाता है। जिसमें कार्य के दौरान अच्छी हिन्दी का उपयोग करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह पहले राजनेताओं के नाम पर था, जिसे बाद में बदल कर राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार और राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार कर दिया गया। राष्ट्रभाषा गौरव पुरस्कार लोगों को दिया जाता है जबकि राष्ट्रभाषा कीर्ति पुरस्कार किसी विभाग, समिति आदि को दिया जाता है

आलोचना

कई हिन्दी लेखकों और हिन्दी भाषा जानने वालों का कहना है कि हिन्दी दिवस केवल सरकारी कार्य की तरह है, जिसे केवल एक दिन के लिए मना दिया जाता है। इससे हिन्दी भाषा का कोई भी विकास नहीं होता है, बल्कि इससे हिन्दी भाषा को हानि होती है। कई लोग हिन्दी दिवस समारोह में भी अंग्रेजी भाषा में लिख कर लोगों का स्वागत करते हैं। सरकार इसे केवल यह दिखाने के लिए चलाती है कि वह हिन्दी भाषा के विकास हेतु कार्य कर रही है। स्वयं सरकारी कर्मचारी भी हिन्दी के स्थान पर अंग्रेजी में कार्य करते नजर आते हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच यह भी है कि विविध कारण बताकर हिन्दी दिवस मनाने का विरोध करने और मजाक उड़ाने वाले यह चाहते हैं कि हिन्दी के प्रति रही-सही अपमत्त्व की भावना भी समाप्त की जाय।

गोंदिया शहर के सार्वजनिक पंडालों के गणेश जी के दर्शन बुलंद गोंदिया पर



नवयुवक गणेश उत्सव मंडल
रामनगर, गोंदिया



शिवाजी गणेश उत्सव मंडल
गांधी प्रतिमा, गोंदिया



न्यू फ्रेंड्स गणेश उत्सव मंडल
गौशाला वार्ड, गोंदिया



श्री सर्वजनिक गणेश उत्सव मंडल
अवंतीबाई चौक, रिंग रोड, गोंदिया



श्री नवरत्न गणेश उत्सव मंडल
गोसाई चौक, रामनगर, गोंदिया



आदर्श गणेश उत्सव मंडल
बसंत नगर, गोंदिया



श्री अपना गणेश उत्सव मंडल,
सुभाष गार्डन के पास, गोंदिया



नवयुवक मिलन गणेश उत्सव मंडल
फणिद्रनाथ ब्रिसेन चौक एन.एम.डी.कॉलेज रोड, गोंदिया



श्री राम गणेश उत्सव समिति
राम मंदिर, रामनगर, गोंदिया



गणेश उत्सव मंडल
जे.एम.हाईस्कूल मैदान, मनोहर चौक, गोंदिया



वृक्षधरा फाउंडेशन की ओर से शिक्षक दिन के उपलक्ष पर किया गया पौधारोपण

बुलंद गोंदिया - शिक्षक दिवस के उपलक्ष पर वृक्षधरा फाउंडेशन की ओर से नागराधाम में पौधारोपण किया गया। वृक्षधरा फाउंडेशन सन 2017 से पर्यावरण संरक्षण के अभियान में लगातार लगा हुआ है एवम गत एक वर्ष से ग्रीन नागराधाम प्रोजेक्ट पर काम शुरू है।

इसी श्रृंखला में इस द्वितीय वर्ष में भी 1100 पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें बादाम, चंपा, जारुल, गुलमोहर

तथा अन्य औषधीय पौधों का पौधारोपण शुरू है। इसी अभियान के अंतर्गत जिला परिषद उपाध्यक्ष यशवंत गणवीर, जिला परिषद सभापति पूजा अखिलेश सेठ, पंचायती समिति सदस्य नंदीनी लिहारे एवम सरला चिखलौंडे, जेष्ठ समाजसेवक अमर बराडे, उपसरपंच नरेश नागरिकर, पुलिस पाटिल, राखी बांते, सुदामा स्कूल के प्राचार्य ठाकुर मैडम तथा समस्त शिक्षकगण, सम्माननीय आशा सेविका एवम

आंगनवाड़ी सेविका तथा ग्रामवासी, विद्यार्थीगण एवम समस्त वृक्षधरा फाउंडेशन के स्वयंसेवक उपस्थित थे।

सभी गणमान्य अतिथियों ने लोगों से अपने परिसर में पौधारोपण करने तथा लगाए गये पौधों के वृक्ष बनने तक देखरेख करने तथा वृक्षधरा फाउंडेशन के इस पर्यावरण संरक्षण के अभियान से जुड़कर अन्य लोगों को इस अभियान से जोड़ने का आवाहन किया।

मेरा हर प्रयत्न जनता की सेवा के लिए - विधायक अग्रवाल

बाढ़ से पीड़ित नांव व्यवसायियों को दी आर्थिक मदद

बुलंद गोंदिया - गत दिनों जिले में भारी वर्षा के वजह से अनेक नुकसान हुए साथ ही भारी बारिश में नदी के समीप बसे गांवों में बाढ़ का काफी असर रहा। इस बाढ़ में रोजमर्रा की जिन्दगी के लिए नांव चलाकर अपना जीवन व्यापन कर रहे कुछ बाढ़ पीड़ितों की नौका बाढ़ के वजह से पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त होकर बाढ़ में बहकर चली गई। जिसके कारण उन्हें अपना जीवन व्यापन करने में काफी दिक्कत निर्माण हो रही थी। साथ ही जब विधायक विनोद अग्रवाल ने बाढ़ग्रस्त इलाको का दौरा किया था, तब उन्हें सरकार से आर्थिक मदद दिलाने हेतु मैं प्रयासरत हूँ और नुकसान का



पंचनामा हेतु सभी नांव व्यवसायी पटवारी को अवगत कराएँ और अपने ओर से उन्हें सांत्वना मदद के तौर पर

आकाश मडावी, जितेन्द्र मेश्राम, स्वदेश केवट इत्यादी इस अवसर पर उपस्थित थे।

वन्य प्राणियों के हमले में मृत के परिजनों को मिलेंगी 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता - वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

बुलंद गोंदिया - जंगली जानवरों के हमले में मारे गए लोगों के परिवारों को 15 लाख की आर्थिक सहायता की राशि को बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गयी है। वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में ऐलान किया। इस संबंध में सरकार का फैसला 23 अगस्त को जारी किया गया है।

राज्य के वन विभाग द्वारा वन संरक्षण के अच्छे प्रयासों के कारण जंगली जानवरों की संख्या काफी हद तक बढ़ गई है। मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की दृष्टि से वन विभाग के माध्यम से वन के निकट के गांवों में रहने वाले नागरिकों को शिक्षित किया जा रहा है और डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना के माध्यम से वनों पर स्थानीय लोगों की निर्भरता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तीन साल 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में जंगली जानवरों के हमले में क्रमशः 47, 80, 86 लोगों की मौत हुई है।

बाघ, तेंदुआ, भैंस, भालू, भेड़िये, सियार, हाथी और जंगली सूअर के हमले में मारे गए लोगों के आश्रित परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि को 15 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। 20 लाख से 10 लाख रु. सावधि जमा आदाता को तत्काल चेक द्वारा और शेष 10 लाख रुपये

उनके मासिक ब्याज वाले संयुक्त खाते में एक राष्ट्रीयकृत बैंक खाते में जमा करने का निर्णय लिया गया है। यदि व्यक्ति स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है तो रु. 5 लाख और यदि व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है तो रु. 1 लाख 25 हजार की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। अगर व्यक्ति थोड़ा घायल होता है तो इलाज का खर्चा चुकाया जाएगा और अगर निजी अस्पताल में इलाज की जरूरत है तो यह सीमा 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति होगी।

जंगली जानवरों के हमले में गाय, भैंस, बैल की मौत होने पर दिए जाने वाले 60 हजार की राशि को बढ़ाकर 70 हजार रुपये कर दिया गया है। भेड़, बकरी और अन्य पशुओं की मृत्यु के मामले में 10,000 को बढ़ाकर 15 हजार रु. कर दिया गया है। गाय, भैंस और बैल को स्थायी विकलांगता के लिए दी जाने वाली राशि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया है। साथ ही गाय, भैंस, बैल, भेड़, बकरी और अन्य पशुओं के घायल होने पर 4,000 की जगह 5000 रु. किया गया है।

जंगली जानवरों के हमले से हुए मानवीय नुकसान और संबंधित परिवारों के आर्थिक बोझ की पृष्ठभूमि में यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

आदिवासी को वनवासी कहना बंद करो रावण दहन बंद करो - ऊषाकिरण ताराम



आदिवासी भाषा शोध संस्थान धनेगाव, बिरसा महिला ब्रिगेड, रानी दुर्गावती महिला मंडल व नेशनल आदिवासी पिपलस फेडरेशन गोंदिया की मांग

बुलंद सवांदादात दरेकसा - आदिवासी लेखिका ऊषाकिरण आत्राम ताराम के नेतृत्व में जिलाधिकारी गोंदिया, उपजिलाधिकारी देशपांडे और जिला पोलीस अधीक्षक गोंदिया के विश्व पानसरे को निवेदन दिया गया। उस वक्त ऊषाकिरण आत्राम ने कहा भारत में रावण दहन किया जाए, यह बेहद गंभीर बात है, क्योंकि आदिवासी समूह रावण को अपना सम्राट और विद्वान मानते, उसकी पुजा करते, वो हमारे श्रद्धास्थान है। लेकिन प्रस्थापित उच्चवर्ग के लोग उसको, दुष्ट, व्याधिचार, गर्विष्ठ और हेय दृष्टि से देखते, समझते और नीच मानते हैं। आदिवासी पूजते हैं। जब जलाते, गाली-गालीच देते तब हमें दुःख होता, हमारी धार्मिक भावनाओं पर आघात पहुंचाता है। इस बुरी प्रथा से समाज में जातिवाद अशांति और बदले की भावना नयी पीढ़ी के लोगों पर पड़ता। क्या रावण इतना बुरा है? आज समाज में रावण से दसगुणा अपराधी, फरेबी, धोखेबाज, बलात्कारी, खुनी, डाकु, चोर, लुटेरे हैं। जिनसे समाज, महिला, आदिवासी, दलित, गरीब लोग भयभीत हैं। उन को सजा क्यों नहीं देते, बलात्कारी को फांसी क्यों नहीं देते, घोटभर पानी के लिए इंद्र मेघवाल का खुन होता। रावण ने तो ऐसा कुछ नहीं किया? और किया तो क्या प्रमाण है इसका? हम आदिवासी का वह प्रिय पुरखा है। इसलिये रावण दहन बंद करो।

जनकल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार और जनसमस्याओं को लेकर भाकपा का जनआंदोलन



बुलंद गोंदिया - आवास योजना, पशुसंवर्धन विभाग, श्रावण बाल, वृद्ध आर्थिक सहायता (पेंशन), तहसील, कचहरीयो के माध्यम से चलाई जा रही योजनाओं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन आदि योजना, कृषि केंद्रों द्वारा खाद, किटनाशक, बिज, आदि वस्तुओं की मनचाहे दामों में बिक्री, जबरान जोतदारो वनजमीन व आदि जमीनो पर किए गये खेती और आवास के पट्टे, धान खरिदी वेन्द्रो वे वे भ्रष्टाचार और सभी जनकल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनआंदोलन छेड़ने के संकल्प के साथ 3-4 सितंबर को साँदड़ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का त्रैवार्षिक जिला प्रतिनिधी सम्मेलन संपन्न हुआ। पार्टी के राज्य सचिवमंडल सदस्य डॉ.शिवकुमार

गनवीर तथा राज्य कार्यकारिनी सदस्य डॉ. हाँसलाल रहांगडाले की प्रमुख उपस्थिति एवम शालुताई कुथे, ललित वैद्य, चरणदास भावे के अध्यक्ष मंडल में हुए सम्मेलन की शुरुवात पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता डोमाजी बावनकर के हस्ते पार्टी का लाल झंडा फहराने के साथ हुई इस दौरान पार्टी के जिला सचिव डॉ.मिलिंद गनवर ने पिछले चार वर्षों का अहवाल एवम आगामी कार्यों का नियोजन की रिपोर्ट रखी जिसपर प्रतिनिधीयो की चर्चा होकर यह पारित किया गया।

सम्मेलन में श्रमिक वर्ग की समस्याएं और आयटक के आंदोलन पर रामचंद्र पाटिल, किसानों के बुनीयादी सवाल तथा जिले के धान उत्पादक की स्थिती तथा किसान सभा के आंदोलन पर करुणा गनवीर, खेत मजदुर, भूमिहीन, मनरेगा तथा ग्रामीण जनता की समस्याओ और खेतमजदुर युनियन के आंदोलन पर प्रल्हाद उके तथा, दलीत, आदिवासीयो पर हो रहे अमानवीय अत्याचार, पद्मोनी, योजनाओ मे कटौती तथा दलीत अधिकार आंदोलन पर अशोक मेश्राम तथा महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार, बलात्कार, घरेलु हिंसा के विषय पर कल्पना डॉंगरे ने प्रस्ताव रखा।

दुसरा मुद्दा है महाराष्ट्र मे आदिवासी को जबरदस्ती से आरएसएस हिन्दू लोग वनवासी कहकर हमारा अपमान करते, हम तो इस धरती के मुलबीज मालिक है। फिर हमे वनवासी इस संबोधन से अपमानित करके, नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते? इस गालीवाले शब्द से हमारा मुल अस्तित्व को धोखा है। इसलिये इस शब्द पर बंदी लगाने व इस शब्द को हटाने की मांग की और महाराष्ट्र मे आदिवासी वनवासी आश्रम स्कूल है। इन सब का नाम गोंडवाना आश्रम स्कूल करो ऐसी मांग की गयी है। निवेदन जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपती, आदिवासी केंद्रिय, और महाराष्ट्र के आदिवासी मंत्री को भी भेजा गया है। इस अवसर पर बिरसा महिला ब्रिगेड की अध्यक्ष मालती किनाके, रानी दुर्गावती महिला मंडल की अध्यक्ष गीता सलामे, गीता तुमराम, लता मडावी, बनिता सलामे, हेमलता आहाके, योगीता गेडाम, सरोता भलावी, बिंदु कोडवते, भावना ऊईके, बबीता कुंबरे, मनिषा कुंबरे, लक्ष्मी फरदे, तुलसीदास कोडापे, सागर पंधरे और पत्रकार अमित वैद्य उपस्थित थे।